MANOHAR PARRIKAR
idsa
MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Commentary

शेख हसीना का राजनीतिक अवसान: एक विश्लेषण

आशीष शुक्ल

सितम्बर 09, 2024

सारांश

बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के एक महीने पूरे होने के बाद भी अंतरिम सरकार देश में वृहद सुधारों का रोडमैप प्रस्तुत करने में विफल रही है|

पिछले महीने की 5 तारीख को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को छात्र आन्दोलन और तेजी से हिंसक हो रही परिस्थितियों के बीच देश छोड़कर जाना पड़ा था| बांग्लादेश के इतिहास में यह पहला मौका था जब एक बेहद ताकतवर प्रतीत हो रही नेत्री को बहुत ही कम समय में उस देश को अलविदा कहना पड़ा जहाँ वह पिछले 15 वर्षो से अधिक समय तक सत्ता के शीर्ष पर विराजमान थी| मुश्किल की इस घड़ी में शेख हसीना अपनी जान बचाने के उद्देश्य से भारत आयीं और तब से यहीं रह रही हैं| इस बात को अब एक महीने हो चुके हैं| शेख हसीना के नेतृव वाली आवामी लीग की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के एक महीने पूरे होने के उपलक्ष में 5 सितम्बर 2024 को छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय के 'राजू मेमोरियल स्कल्पचर' से 'शहीदी मार्च' के रूप में एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें हजारों छात्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया|[1] वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार अस्तित्व में है जिसके ऊपर स्थितियों को नियंत्रित करते हुए व्यवस्था को सामान्य करने की जिम्मेदारी है| बांग्लादेश के संविधान के अनुसार जातीय संगसद (बांग्लादेश की संसद) के विघटन के 90 दिनों के अन्दर आम चुनाव हो जाने चाहिए|

शहीदी मार्च के समापन पर 'एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट' के अबू बकर मजूमदार ने अंतरिम सरकार से जल्द से जल्द देश में सुधारों का रोडमैप जारी

[1] **"Unveil Roadmap to Reform Immediately"**, *Daily Star*, 5 September 2024.

करने की माँग की| इसके अतिरिक्त उनकी अन्य माँगों में छात्र आन्दोलन के दौरान शहीद हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक और कानूनी मदद देना, दोषी और भ्रष्ट अधिकारियों और आवामी लीग सरकार प्रशासन के अन्दर मौजूद समर्थकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जन संहार (Mass Killing) के लिए दोषी लोगों को गिरफ्तार कर दण्डित करना, और शेख हसीना के आधिकारिक निवास 'गोनों भबन' को 'जुलाई मेमोरियल' घोषित करना शामिल है|[2]

शेख हसीना शासन की कार्यप्रणाली

शेख हसीना के राजनीतिक अवसान पर बहुत से विश्लेषकों और बांग्लादेश पर करीबी नजर रखने वाले विद्वानों में एकमतता का अभाव है| ज्यादातर विश्लेषक एवं विद्वान इस बात पर सहमत प्रतीत होते हैं कि आवामी लीग का शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर शेख हसीना, इस हालिया हिंसा और उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार हैं| इनमें से कुछ इसे हालिया 'कोटा रिफ़ॉर्म आन्दोलन' और आवामी लीग नेतृव द्वारा इसके प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने से जोड़कर देखते हैं, तो वहीँ अन्य इसे शेख हसीना के 15 वर्षीय शासन के दौरान अपनाई गयी नीतियों एक वृहद् आलोक के अंतर्गत रखते हैं| हालाँकि कुछ विश्लेषक ऐसे भी हैं जो शेख हसीना के निष्कासन के पीछे एक तरह की साजिश देखते हैं| ऐसे लोगों का मानना है कि चूँकि शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद एक बेहद ताकतवर राष्ट्र

[2] Ibid.

का पिछलग्गू बनाने को तैयार नहीं थी इसलिए एक साजिश के तहत चालाकी से छात्र आन्दोलन के पीछे छिपकर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया|

'बिन पेंदी के लोटे' से 'इकोनोमिक मिरेकल' तक

बांग्लादेश के इतिहास एवं वर्तमान गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने वाले विश्लेषकों की मानें तो शेख हसीना के राजनीतिक अवसान का मूल कारण उनके 15 वर्षीय शासन के दौरान अपनाए गए तौर-तरीकों में खोजा जा सकता है| शेख हसीना के शासन के दो प्रमुख पहलू थे| पहले का सम्बन्ध उनके द्वारा अपनाई गयी आर्थिक नीतियों एवं आम जनमानस के विकास के लिए चलाई गयी परियोजनाओं से है, जबकि दूसरे का सम्बन्ध लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं की लगातार की गयी अवहेलना से है| यह उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में किए गए सुधारों और विकास के कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि जिस बांग्लादेश को कभी हेनरी किसिंजर ने 'बिन पेंदी का लोटा' कहा था और कुछ अन्य लोगों ने उसे 'डेवलपमेंटल गिनी पिग' की संज्ञा से नवाजा था, उसी बांग्लादेश को पिछले कुछ वर्षों से 'इकोनॉमिक मिरैकल' कहकर संबोधित किया जाने लगा था| दक्षिण एशिया में भारत के बाद अगर किसी अन्य अर्थव्यवस्था की बात की जाती थी तो वह निसंदेह बांग्लादेश ही था|

बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल में होने वाले सकारात्मक बदलावों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती| यह उनके कार्यकाल में ही संभव हो पाया कि

बांग्लादेश जो अत्यंत ही असामान्य परिस्थितयों के बीच सन 1971 में अस्तिव में आया, वह आगे चलकर न केवल दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण एवं रेजिलिएन्ट अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा बल्कि बहुत से सामाजिक एवं मानव विकास के पैमानों पर उसका प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में भारत सहित अन्य देशों से अच्छा हो सका| चाहे वह प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो (Per Capita GDP), जीवन प्रत्याशा हो (Life Expectancy), लिंग-समानता (Gender Parity), या महिला कामगारों की आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता (Female Workforce Participation), बांग्लादेश का प्रदर्शन भारत से अच्छा था/है|

अगर वर्ष 2020 को कोविड-19 के कारण एक अपवाद मान लें तो वर्ष 2010 से लेकर आज तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की विकासदर 5.5% से नीचे नहीं रही| आई.एम.एफ. के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में देश की वास्तविक जी.डी.पी. विकासदर 7.9% थी जो कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण 2020 में केवल 3.4% रह गयी|[3] हालाँकि कोविड-19 के प्रभाव के कम होते ही अर्थव्यवस्था की विकासदर फिर से बढ़ने लगी और 2023 में 6% तक पहुँच गयी|[4] कभी-कभी आकड़े हमें पूरी वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाते या दूसरे शब्दों में आकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि उनका एक पक्ष तो नमूदार हो जबकि दूसरे पक्ष को अँधेरे में रखा जा सके| मार्क तूली का एक प्रसिद्ध कथन है कि संसार में तीन तरह के झूठ होते हैं; झूठ (Lies), महा-झूठ (Damned

[3] **"Real GDP Growth: Annual Percentage"**, International Monetary Fund, 2024.
[4] Ibid.

Lies) और आकड़े (Statistcis). बांग्लादेश के सन्दर्भ में इसे समझने के लिए हमें फिर से एक अन्य आकड़े पर निर्भर होना पड़ेगा जो हमें उसके दूसरे पक्ष को दिखाता है|

वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति (Inflation) की दर 9.3% रही जोकि वर्ष 2011-12 के बाद सर्वाधिक है| बांग्लादेश बैंक के अनुसार जुलाई 2024 में मुद्रास्फीति बढ़कर 9.9% हो गयी|[5] साथ ही देश के युवाओं में बेरोजगारी की दर रिकार्ड स्तर पर पहुँच गयी| 170 मिलियन की आबादी वाले बांग्लादेश में 18-24 साल के 18 मिलियन युवा न तो किसी तरह के रोजगार में हैं और न ही किसी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत हैं|[6] वर्तमान समय में जारी राजनीतिक उथल-पुथल का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है| बिना राजनीतिक स्थायित्व के आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना किसी भी परिस्थिति में आसान नहीं होगा|

लोकतान्त्रिक मूल्यों का लगातार विघटन

शेख हसीना के शासन का दूसरा पहलू, जिसे उनके राजनीतक अवसान के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उनके द्वारा देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं की अवमानना एवं अवहेलना से सम्बंधित है| लार्ड ऐक्टन का एक

[5] **"Current Inflation"**, Bangladesh Bank, July 2024.
[6] Chietigj Bajpaee and Patrick Schroder, **"Sheikh Hasina's Departure Exposes the Fractures in Bangladesh's Politics"**, Chatham House, 13 August 2024.

प्रसिद्ध कथन है "शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है|" उन्ही का एक और कम प्रसिद्ध कथन है "प्राधिकार (Authority) जो स्वतंत्रता (Liberty) के लिए अस्तित्व में न हो, वह प्राधिकार (Authority) नहीं ताकत (Force) है|" सन 2009 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना एक लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि से उत्तरोत्तर एक सत्तावादी (Authoritarian) नेत्री होती चली गईं| इस ट्रेंड में 2014 के बाद काफी तेजी आई और धीरे धीरे शेख हसीना लार्ड ऐक्टन के दोनों कथनों को चरितार्थ करती हुए प्रतीत हुईं| बांग्लादेश में शेख हसीना का जिस तरह से राजनीतिक अवसान हुआ वह कई कारणों से महत्वपूर्ण है|

आवामी लीग के इतिहास के सर्वाधिक कद्दावर नेता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश के एक अलग देश बनने में महती भूमिका निभाई, के राजनीतिक दल का उनकी अपनी बेटी के नेतृत्व में जो हश्र हुआ वह किसी के लिए भी अविश्वसनीय हो सकता है| जिस तरह से छात्र आन्दोलन में शामिल लोगों ने, शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के पश्चात्, बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जगह-जगह लगी बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं को खण्डित किया वह अत्यंत दुखद है| बहुत से बांग्लादेशी, जो शेख हसीना की बेदखली का जश्न मना रहे थे, बंगबंधु की प्रतिमाओं के तोड़े जाने से दुखी हुए| कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए तो वहीँ कुछ अन्य लोगों ने इसका ठीकरा शेख हसीना पर फोड़ते हुए यह आरोप लगाया कि वह स्वयं तो बंगबंधु के दिखाए रास्ते पर नहीं चली और हमेशा उनकी बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं के पीछे अपनी नाकामियों को छिपाने

का प्रयास किया| इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है कि शेख हसीना के शासन के तौर-तरीकों से अंधिकांश लोग सहमत नहीं थे| इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आई.सी.जी.) ने हाल ही में कहा था कि शेख हसीना के कार्यकाल में जातीय संगसद (बांग्लादेश की संसद) एक रबर स्टैम्प बन गयी थी, सिविल सेवा और न्यायपालिका अत्यधिक ध्रुवीकृत हो गई थी, तथा मीडिया एवं नागरिक समाज को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता था|[7]

निष्कर्ष

मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार इस वक्त अनेकों झंझावातों से जूझ रही है| एक ओर उनके समक्ष क़ानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है तो वहीँ दूसरी ओर छात्र आन्दोलन से उपजी मांगों को पूरा करने का दबाव है| इन सबके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है एक शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराकर सत्ता की चाभी देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपना| एक ऐसे समय में जब देश की लगभग सभी संस्थाएं, विशेषकर पुलिस, न्यायपालिका, और नौकरशाही अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं, सरकार का कार्य किसी भी दृष्टिकोण से आसान नहीं रहने वाला है| वैसे तो संविधान 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की बाध्यता लगाता है लेकिन मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के समक्ष चुनौतियों

[7] **"Bangladesh: The Long Road Ahead"**, International Crisis Group, 7 August 2024.

को देखते हुए अगले दो वर्ष में भी आम चुनाव होने पर संशय है| अब यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरिम सरकार अपनी काबिलियत एवं जिम्मेदारियों तथा लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बीच कैसे सामंजस्य बिठाती है|

About the Author

Dr. Ashish Shukla is Associate Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2024

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses